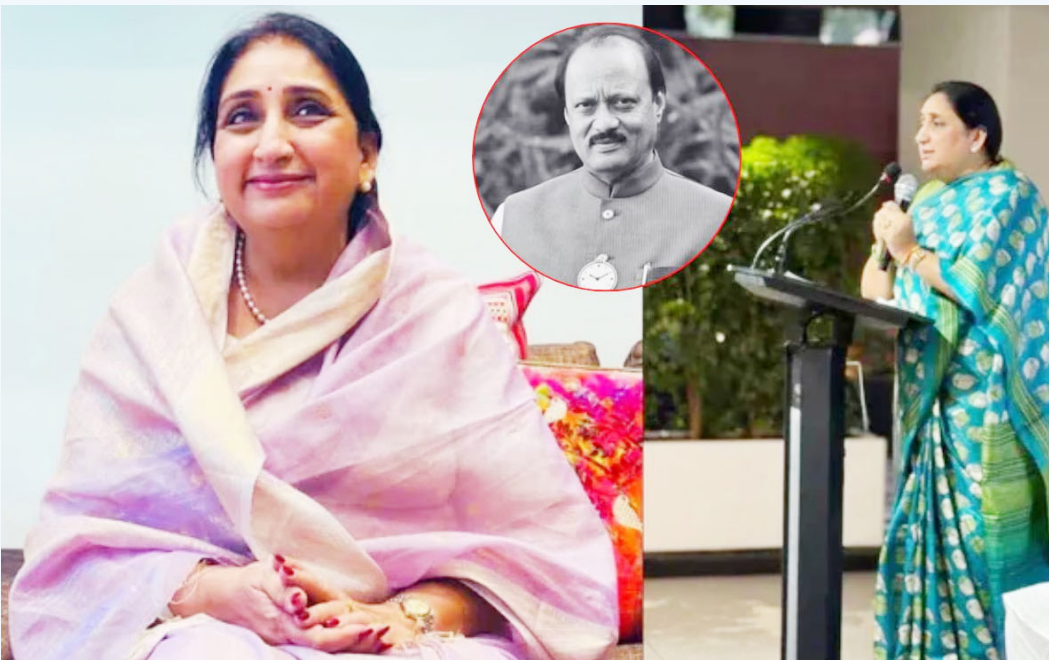


# शोक के साए में सत्ता की नई सुबह, सुनेत्रा पवार के हाथों में महाराष्ट्र की कमान

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ देखा है, जहां गहरे शोक, असमय त्रासदी और सत्ता की अनिवार्यता एक साथ आ खड़ी हुई हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु ने न सिर्फ उनके परिवार और समर्थकों को तोड़ दिया, बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है, बारामती से मुंबई तक सन्नाटा और संवेदनाओं का ज्वार है, लेकिन इसी शोक के बीच सत्ता के संतुलन और सरकार की स्थिरता बनाए रखने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में यह लगभग तय हो चुका है कि अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शुक्रवार शाम तक राजनीतिक गलियारों में यह संदेश स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट ने नेतृत्व की बागडोर सुनेत्रा पवार को सौंपने का मन बना लिया है। वरिष्ठ नेता और मंत्री छान भुजबल ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने

भी सैद्धांतिक तौर पर इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। शनिवार सुबह 11 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें औपचारिक रूप से नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो उसी दिन उनके शपथ ग्रहण की भी संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे घंटों की गहन चर्चा, संतुलन की राजनीति और संभावित टूट से बचने की रणनीति रही है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई से सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार से सीधी बातचीत की। इसी बातचीत में पहली बार औपचारिक रूप से उपमुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया। शुरुआती तौर पर सुनेत्रा पवार ने व्यक्तिगत शोक और परिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए हिचक दिखाई, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं, बल्कि एनसीपी और सरकार की स्थिरता का मुद्दा है। अंततः पार्टी और राज्यहित को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पद स्वीकार



करने पर सहमति जता दी। इस पूरे घटनाक्रम में दिलीप वलसे पाटिल की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। वे ऐसे नेता माने जाते हैं, जिन पर शरद पवार और अजित पवार—दोनों खेमों का भरोसा रहा है। प्रफुल्ल पटेल के आग्रह पर उन्होंने

अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और तुरंत मुंबई पहुंचे। उन्हीं की पहल पर एनसीपी विधायकों की निर्णायक बैठक बुलाई गई, ताकि किसी भी तरह की गुटबाजी या असंतोष को उभरने से पहले ही रोका जा सके। पार्टी के अंदर यह स्पष्ट राय थी कि यदि यह जिम्मेदारी किसी

और को दी जाती, तो विधायकों में टूट और खींचतान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर भी उच्चस्तरीय राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलीं। प्रफुल्ल पटेल, छान भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे जैसे

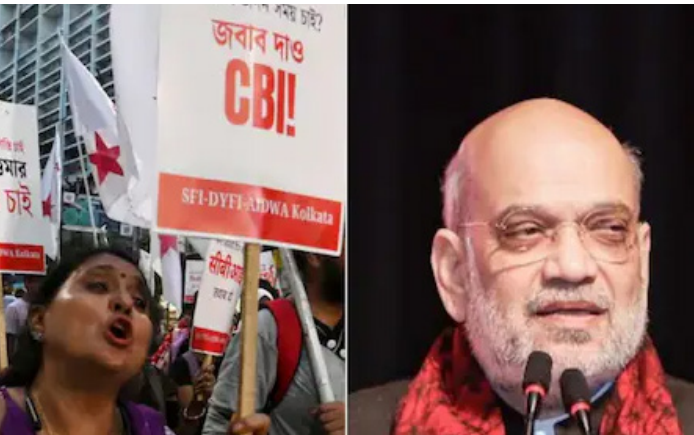
दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करीब डेढ़ घंटे तक चर्चा की। इस बैठक में सरकार के भविष्य, एनसीपी की भूमिका और अजित पवार के बाद उत्पन्न राजनीतिक शून्य को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। देर शाम एनसीपी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में छान भुजबल ने साफ किया कि यदि विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाता है, तो शपथ ग्रहण में कोई देरी नहीं की जाएगी। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उपमुख्यमंत्री पद की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। इस दिशा में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। अजित पवार के निधन से खाली हुई बारामती विधानसभा सीट को लेकर पार्टी में स्पष्ट रणनीति है कि सुनेत्रा पवार वहीं से चुनाव लड़ेंगी। बारामती सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि पवार परिवार और एनसीपी की राजनीतिक पहचान का प्रतीक रही है। माना जा रहा है कि इस सीट से चुनाव लड़कर सुनेत्रा पवार न केवल अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी एक भावनात्मक

संबल देंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम पर संतुलित बयान देते हुए कहा है कि जो भी निर्णय होगा, वह एनसीपी का आंतरिक फैसला होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार के सहयोगी के रूप में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे मामला अजित पवार के परिवार का हो या पार्टी का, सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। उनके इस बयान को सत्ता में स्थिरता और गठबंधन धर्म के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इधर, दिन भर मुंबई से अमरावती तक बैठकों का दौर चलता रहा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शुक्रवार सुबह फडणवीस से मिलने उनके आवास वर्या बंगले पहुंचे, जहां उपमुख्यमंत्री पद और विभागों के संतुलन को लेकर चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर, सुनेत्रा पवार ने बारामती में अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा को बुलाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम संकेत देता है कि सुनेत्रा पवार अब सक्रिय राजनीति में पूरी तरह उतरने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी हैं। इस बीच, अजित पवार की विमान दुर्घटना को लेकर विपक्ष ने भी सवाल

खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेठ्ठेवार ने इस हादसे के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे समय में, जब एनसीपी के दोनों गुटों के एकीकरण की चर्चाएं तेज थीं, इस तरह की घटना कई संदेह पैदा करती है। एनसीपी के भीतर भी कुछ नेताओं ने संकेत दिया है कि अजित पवार दोनों गुटों के विलय को लेकर गंभीर प्रयास कर रहे थे और उनके पास पार्टी के भविष्य का एक स्पष्ट रोडमैप था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त एक ऐतिहासिक और संवेदनशील दौर से गुजर रही है। एक ओर एक बड़े नेता की असमय विदाई का शोक है, तो दूसरी ओर सत्ता की जिम्मेदारी संभालने की चुनौती। यदि सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं, तो यह न केवल राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने का क्षण होगा, बल्कि पवार परिवार और एनसीपी के लिए भी एक नए राजनीतिक अধ্যाय की शुरुआत मानी जाएगी। शोक, संवेदना और सत्ता—तीनों के बीच संतुलन साधना अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

## कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म-हत्या मामले में पीड़िता का परिवार सीबीआई जांच से नाखुश, न्याय की मांग जोर पकड़ रही

(जीएनएस)। नार्थ 24 परगना। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई शर्मनाक दुष्कर्म और हत्या की घटना की गुंज अब भी समाज और परिवार दोनों में गहरे सदमे का कारण बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, लेकिन पीड़िता के परिवार ने हालिया घटनाक्रम और न्याय प्रक्रिया से अपनी नाराजगी जाहिर की है। परिवार का आरोप है कि न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कोर्ट की सुनवाई में गंभीर procedural खामियां रही हैं, जिससे उन्हें न्याय मिलने में आशंका है। पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, जबकि मामले में कई और पहलू और आरोपी हैं। उनके अनुसार, सुनवाई अधिकांशतः बंद कमरे में की गई थी और परिवार को कोर्टरूम में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे वे मामले की वास्तविक स्थिति और गवाहों के बयान को सही ढंग से नहीं देख सके।



उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अदालत में उपस्थित होकर मामले को नजदीक से देखने और तथ्यों को सामने रखने का मौका मिलता, तो कई विरोधाभासी बयानों को सही तरीके से सामने लाया जा सकता था। पीड़िता के माता-पिता ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ या चुनावी कदम नहीं है। पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया, लेकिन उनका मकसद सिर्फ

न्याय पाना है। परिवार ने केंद्र सरकार से भी मुलाकात की इच्छा जताई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना बनाई है, ताकि अपनी चिंताओं और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार की जरूरतों को सीधे उनसे साझा किया जा सके। 9 अगस्त 2024 को पीजी द्वितीय वर्ष

प्रश्न खड़े कर गई थी। विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में पीड़िता और उनके परिवार की सुरक्षा, न्याय और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अब परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो, और कोर्ट में सुनवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उनके अनुसार, न्याय मिलने तक कोई राजनीतिक कदम या अन्य दबाव उनकी प्राथमिकता नहीं है। यह मामला राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक संवेदनशील चुनौती बन गया है, जो न्याय व्यवस्था की जवाबदेही और सामाजिक संवेदनशीलता की परीक्षा ले रहा है। इस बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि पीड़िता के परिवार को उचित सुरक्षा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे निर्भय होकर न्याय की मांग कर सकें और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

## सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा की नई इबारत : मासिक धर्म को मौलिक अधिकार मानकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की करोड़ों छात्राओं के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाला एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सम्मान को एक ही सूत्र में बांध दिया है। शीर्ष अदालत ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि सुरक्षित और गरिमापूर्ण मासिक धर्म प्रबंधन के बिना किसी लड़की के लिए सम्मानजनक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि वर्षों से चुपचाप झेली जा रही सामाजिक उपेक्षा, असमानता और वर्जनाओं के खिलाफ एक मजबूत संवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन को पीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि मासिक धर्म कोई निजी या हाशिए का विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार से जुड़ा प्रश्न है। अदालत ने माना कि स्वच्छता, सुरक्षित उत्पादों और निजता के अभाव में मासिक धर्म केवल शारीरिक कष्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मानसिक तनाव, आत्मसम्मान की क्षति और शिक्षा से दूरी का कारण भी बनता है। इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने देश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले का सबसे सख्त और प्रभावीत पहलू यह है कि अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। यानी अब यह कोई वैकल्पिक या



कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि कानूनी बाध्यता होगी। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार की 'राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति' को तीन महीने के भीतर प्रभावी रूप से लागू करें। यह आदेश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा, ताकि किसी भी लड़की को केवल भौगोलिक या आर्थिक कारणों से पीछे न रहना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं केवल सैनिटरी पैड की उपलब्धता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह स्कूल परिसरों के बुनियादी ढांचे से भी गहराई से जुड़ी हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि हर स्कूल में छात्राओं और छात्रों के लिए अलग-अलग, स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय होने चाहिए, जिनमें पानी और साबुन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अदालत ने माना कि बिना स्वच्छ शौचालयों के सैनिटरी उत्पाद देना अधूरा समाधान है, क्योंकि इससे छात्राओं की निजता और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही स्कूल परिसरों में 'मासिक धर्म' के संदर्भ में पानी और साबुन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अदालत ने आदेश दिया गया है। इन कॉर्नरों में केवल सैनिटरी पैड ही नहीं, बल्कि आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त

सहपाठियों के मुकाबले असमान स्थिति में खड़ा कर देती है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल छात्राओं का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता का पैमाना है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि लड़कों और पुरुष शिक्षकों को भी मासिक धर्म से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों और मानवीय दृष्टिकोण के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि शर्म, भ्रम और भेदभाव की मानसिकता को खत्म किया जा सके। कोर्ट ने माना कि जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक केवल बुनियादी सुविधाएं भी अधूरी साबित होंगी। इस फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में आदेश का पालन हो रहा है या नहीं और कहीं लापरवाही पाए जाने पर समय रहते कार्रवाई की जाए। अदालत ने संकेत दिए हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया होगी, न कि एक बार का औपचारिक अनुपालन। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले को भारत में महिला अधिकारों और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। उनका मानना है कि यह आदेश न केवल स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बल्कि लंबे समय में बालिकाओं के ड्रॉपआउट रेट को भी कम करेगा। यह फैसला उन लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आज भी मासिक धर्म को लेकर चुपड़ी, शर्म और असुविधा के बीच पड़ाई करने को मजबूर हैं। यह स्थिति उन्हें उनके पुरुष

सहपाठियों के मुकाबले असमान स्थिति में खड़ा कर देती है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल छात्राओं का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता का पैमाना है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि लड़कों और पुरुष शिक्षकों को भी मासिक धर्म से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों और मानवीय दृष्टिकोण के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि शर्म, भ्रम और भेदभाव की मानसिकता को खत्म किया जा सके। कोर्ट ने माना कि जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक केवल बुनियादी सुविधाएं भी अधूरी साबित होंगी। इस फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में आदेश का पालन हो रहा है या नहीं और कहीं लापरवाही पाए जाने पर समय रहते कार्रवाई की जाए। अदालत ने संकेत दिए हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया होगी, न कि एक बार का औपचारिक अनुपालन। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले को भारत में महिला अधिकारों और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। उनका मानना है कि यह आदेश न केवल स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बल्कि लंबे समय में बालिकाओं के ड्रॉपआउट रेट को भी कम करेगा। यह फैसला उन लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आज भी मासिक धर्म को लेकर चुपड़ी, शर्म और असुविधा के बीच पड़ाई करने को मजबूर हैं। यह स्थिति उन्हें उनके पुरुष

## तेलंगाना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, नागरकुर्नूल में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या से हड़कंप

(जीएनएस)। नागरकुर्नूल। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले से सामने आई आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या की घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे राज्य में प्रशासनिक संवेदनशीलता और पशु अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थुम्पेल्लू गांव में बीते करीब दस दिनों के भीतर सौ से अधिक आवारा कुत्तों को कथित रूप से जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिए जाने का मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश और भय का माहौल है। इस अमानवीय कृत्य को लेकर पशु प्रेमी संगठनों के साथ-साथ आम ग्रामीणों ने भी गहरी नाराजगी जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह शिकायत स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी एनिमल क्रूता रोकथाम सहायक मुद्रावध प्रीति द्वारा चारपका पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव में सुनियोजित तरीके से आवारा कुत्तों को निशाना बनाया गया और यह सब किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि लगातार कई दिनों तक चलाया गया अभियान था। बताया गया है कि गांव के अलग-अलग



हिस्सों में कुत्तों को पकड़कर उन्हें जहरीले इंजेक्शन दिए गए, जिससे उनकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई। एफआईआर के मुताबिक, 27 जनवरी को इस घटना की पहली टोस जानकारी सामने आई थी, जब स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में कुत्तों के अचानक गायब होने और कुछ स्थानों पर मृत कुत्तों के पड़े होने की सूचना दी। इसके बाद जब पशु प्रेमी संगठनों ने पड़ताल शुरू की, तो मामला और भी भयावह नजर आया। आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई को गांव के सरपंच और पंचायत सचिव के निर्देश पर अंजाम दिया गया। शिकायत में एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है, जिसमें सरपंच कथित तौर पर यह स्वीकार करते हुए सुने जा रहे हैं कि कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा गया और इसके

संकेत मिलता है कि यह घटना किसी आवेश या अचानक लिए गए फैसले का परिणाम नहीं, बल्कि सुनियोजित और संगठित तरीके से की गई कार्रवाई थी। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का खुला उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि मारे गए कुत्तों के शवों को छिपाने और सव्त मिटाने की कोशिशें की गईं। आरोप है कि ग्राम पंचायत कर्मचारी रवि ने मृत कुत्तों के शवों को उठाकर गांव से बाहर ले जाने में भूमिका निभाई। वहीं एक अन्य कथित बातचीत में

गोपी नामक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है कि छिपे दस दिनों से लगातार कुत्तों को जहर दिया जा रहा था। सरपंच के कथित बयान में यह भी कहा गया है कि मृत कुत्तों के शवों को गांव से करीब दो किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया गया, ताकि गांव में कोई हलचल न हो और मामला दबा रहे। इस घटना के सामने आने के बाद गांव में डर और असहजता का माहौल है। कई ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों से कुछ समस्याएं जरूर थीं, लेकिन इस तरह सामूहिक हत्या किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि यदि समस्या थी, तो प्रशासनिक स्तर पर नसबंदी, टीकाकरण या पुनर्वास जैसे वैधानिक और मानवीय उपाय अपनाए जा सकते थे। इसके बजाय हिंसक और गैरकानूनी रास्ता अपनाया गांव की छवि और सामाजिक मूल्यों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। पशु प्रेमी संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इस मामले में उदाहरणात्मक सजा नहीं दी गई, तो यह एक खतरनाक मिसाल को उठाकर गांव से बाहर ले जाने में भूमिका निभाई। वहीं एक अन्य कथित बातचीत में

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये





## संपादकीय

## आर्थिक सर्वेक्षण ने लचीलापन पर दिया जोर

देश में आम बजट से पहले सामने आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला व गतिशील बनाने पर बल दिया गया है। यह सर्वेक्षण उन चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है, जिनके लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी के 7.4 रहने का भरोसा जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास वृद्धि दर के 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान में सीमापारक तनाव, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से यह सावधानीपूर्वक दशाया गया आशावादी दृष्टिकोण घरेलू मांग, उपभोग और निवेश की मजबूती को ही दर्शाता है। इसके बावजूद कि तमाम बाहरी जोखिम विद्यमान हैं, मसलन टैरिफ को लेकर आपूर्ति शृंखला में तनाव व देश की अपेक्षाओं का संतुलन बनाना शामिल है। यह सार्थक है कि सर्वेक्षण यथार्थवाव को नजरअंदाज नहीं करता है, जो यह भी दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पूंजी प्रवाह व मुद्रा की ताकत से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। यह भी हकीकत है कि एआई जैसी नई तकनीकों से होने वाले लाभ असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके लिये भी सहायक मानव संसाधन और विनियामक ढांचे की जरूरत होती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां श्रम शक्ति का बाहुल्य है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश होने का लाभ उठाएं। इसके लिये कौशल विकास को प्राथमिकता देने की सख्त जरूरत है, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों के जरिये विश्व में आर्थिक स्पर्धा का मुकाबला कर सके। ये कदम हमारे निर्यात बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं। कालांतर में ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है।

इसमें दो राय नहीं है कि हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी अभियान को तरजीह देने से लेकर रणनीतिक लचीलेपन और रणनीतिक अनिवार्यता भारत की आर्थिक क्षमता की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की साख को अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाए। निस्संदेह, विश्व में भारतीय उत्पाद ‘खरीदने के बारे में सोचने’ से स्थिति को ‘बिना सोचे भारतीय उत्पाद खरीदने’ वाली सोच विकसित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इस स्थिति के लिये हमें विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिक्रिद्धता की सख्त जरूरत होगी। निस्संदेह, हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ संपन्न हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर अर्थव्यवस्था में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। सर्वेक्षण में इस बाबत कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस एफटीए के सिरे चढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी को कितना मिलता है। सवाल यह भी है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रीहेंकालिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। सर्वेक्षण में इस बाबत कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस एफटीए के सिरे चढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी को कितना मिलता है। सवाल यह भी है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी के जीवन को बढ़ाते में कितना मददगार होगा। एआई और तकनीक क्रांति के दौर में भारतीय विपुल श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है। भारत दुनिया में सबसे युवा श्रम शक्ति वाला देश है तो क्या हम उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप रोजगार देने में सक्षम होंगे, ताकि वे विकसित भारत के संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। जरूरत इस बात की है कि देश में बेरोजगारी की दर कम हो और युवाओं के विदेश पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये पहल की जाए। वहीं दूसरी ओर फिसलन वाली जमीन पर चलते हुए सर्वेक्षण में दो दशक पुराने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव की मंशा जतायी गई है। निस्संदेह, ऐसे किसी बदलाव का आधार तार्किक होना चाहिए।

## अभियान

# महादेव के चरणों में जीवन: शुक्र प्रदोष व्रत की भक्ति से खुलता कृपा का द्वार

सनातन परंपरा में भक्ति केवल पूजा-पाठ का नाम नहीं है, भक्ति वह भाव है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को त्यागकर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब यह समर्पण सच्चा होता है, तब जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। शुक्र प्रदोष व्रत ऐसा ही एक पावन अवसर है, जो भक्त को भगवान शिव के अत्यंत निकट ले जाता है। यह व्रत केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण है। शिव को भोलेनाथ प्रदोष व्रत का संबंध भगवान शिव से है, जो करुणा, वैराग्य और क्रत्याण के प्रतीक हैं। जब यह व्रत शुक्रवार को पड़ता है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्रवार शुक्र ग्रह और देवी शक्ति का दिन माना जाता है। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत और शक्ति, वैराग्य और सौंदर्य, त्याग और सुख—इन सबका दिव्य संतुलन प्रस्तुत करता है। यह संतुलन ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है।

शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न और कृपालु होते हैं। सूर्यास्त के बाद का यह समय दिन और रात के संघ का प्रतीक है। यह

# “

## माखनलाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, स्वतंत्रता सेनानी अनेक भूमिकाओं में सामने आते हैं।

## वे अप्रतिम वक्ता भी थे। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा-“हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना (भाषण) तो माखनलाल जी ही जानते हैं।”

## प्रेरणा

# शोर के बीच स्थिर मन: एकाग्रता की अदृश्य

मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। आज का समय तेज है, प्रतिस्पर्धा है और सूचनाओं से भरा हुआ है। हर क्षण कुछ न कुछ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है। मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की सूचनाएँ, काम का दबाव, भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृतियाँ—इन सबके बीच मन का एक जगह टिक पाना कठिन होता जा रहा है। ऐसे समय में एकाग्रता केवल सफलता का साधन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति की अनिवार्य शर्त बन गई है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक लॉर्ड मोनवर्न का प्रसंग इसी सत्य को गहराई से उजागर करता है। वे अपने समय के ऐसे चिकित्सक थे जो अत्यधिक भीड़-भाड़ और शोरगुल के बीच भी रहना नहीं है। यह मन को वह अवस्था है जिसमें चेतना पूरी तरह वर्तमान क्षण में स्थापित हो जाती

एकाग्रता का अर्थ केवल किसी वस्तु को घूरने रहना नहीं है। यह मन को वह अवस्था है जिसमें चेतना पूरी तरह वर्तमान क्षण में स्थापित हो जाती

# “

## माखनलाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, स्वतंत्रता सेनानी अनेक भूमिकाओं में सामने आते हैं। वे अप्रतिम वक्ता भी थे। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा-“हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना (भाषण) तो माखनलाल जी ही जानते हैं।”

## प्रेरणा

# शोर के बीच स्थिर मन: एकाग्रता की अदृश्य

है। जब मन वर्तमान में होता है, तब न तो अतीत की पछतावे की पीड़ा उसे विचलित करती है और न ही भविष्य की आशंकाएँ उसे डराती हैं। लॉर्ड मोनवर्न के लिए ऑपरेशन का क्षण पूर्ण उपस्थिति का क्षण था। उस समय उनके लिए न प्रशंसा का महत्व था, न आलोचना का भय। उनका संपूर्ण अस्तित्व उस एक कार्य में समर्पित हो जाता था। आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम शारीरिक रूप से एक जगह होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कई जगह भटक रहे होते हैं। हम पढ़ते समय भविष्य की योजनाएँ सोचते हैं, काम करते समय मोबाइल देखते हैं और परिवार के साथ होते हुए भी मन कहीं और भटका रहता है। यह विभाजित ध्यान धीरे-धीरे हमारी कार्यक्षमता को कम कर देता है। एकाग्रता हमें यह सिखाती है कि एक समय में एक ही कार्य को पूरी निष्ठा और सजगता के साथ किया जाए। यही सिद्धांत लॉर्ड मोनवर्न के जीवन में दिखाई देता है। उनके कथन में “भगवान” शब्द विशेष महत्व रखता है। यहाँ भगवान किसी धार्मिक सीमा रेखा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह आस्था, उत्तरदायित्व और विनम्रता का प्रतीक है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी बड़े उद्देश्य या उच्च चेतना के सामने उत्तरदायी है, तब उसका अहंकार स्वतः कम होने लगता है। अहंकार के कम होते ही मन हल्का हो जाता है और एकाग्रता सहज रूप से रहना नहीं है। यह मन को वह अवस्था है जिसमें चेतना पूरी तरह वर्तमान क्षण में स्थापित हो जाती

# “

## माखनलाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, स्वतंत्रता सेनानी अनेक भूमिकाओं में सामने आते हैं। वे अप्रतिम वक्ता भी थे। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा-“हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना (भाषण) तो माखनलाल जी ही जानते हैं।”

## प्रेरणा

# शोर के बीच स्थिर मन: एकाग्रता की अदृश्य

और इसी भावना ने उनके ध्यान को अडिग बनाए रखा। एकाग्रता का सीधा संबंध भय से भी है। भय मन को भविष्य में ले जाता है—भूलती का भय, असफलता का भय, परिणाम का भय। जब मन भय से ग्रस्त होता है, तब वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह टिक नहीं पाता। लॉर्ड मोनवर्न की एकाग्रता इसलिए भी अटूट थी क्योंकि वे भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य में लीन रहते थे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना सीख लिया था और परिणाम को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दिया था। यह भाव मन को तनाव से मुक्त करता है और कार्य को सहज बना देता है। यह धारणा कि शांति केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही संभव है, पूरी तरह भ्रम है। वास्तव में शांति भीतर की अवस्था है, परिस्थितियों की नहीं। हमें भीतर शांति होती है, तब बाहर की अव्यवस्था भी हमें विचलित नहीं कर पाती। ऑपरेशन थियटर की भीड़ और शोर लॉर्ड मोनवर्न के लिए बाधा नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर एक मौन था। यही आंतरिक मौन एकाग्रता की भूमि है, जहाँ से सटीक निर्णय, स्थिर हाथ और स्पष्ट दृष्टि उत्पन्न होती है। एकाग्रता को विकसित करना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह निरंतर अभ्यास और अनुशासन से आती है। सबसे पहला अभ्यास है—स्पष्टता। हमें स्वयं से यह स्पष्ट करना होता है कि इस क्षण हमारा मुख्य कार्य क्या है। दूसरा अभ्यास

# “

## माखनलाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, स्वतंत्रता सेनानी अनेक भूमिकाओं में सामने आते हैं। वे अप्रतिम वक्ता भी थे। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा-“हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना (भाषण) तो माखनलाल जी ही जानते हैं।”

## प्रेरणा

# शोर के बीच स्थिर मन: एकाग्रता की अदृश्य

है—मन की सजगता। जब मन भटकने लगे, तो उसे कठोरा से नहीं, बल्कि कोमलता से वापस वर्तमान में लाना चाहिए। श्वास पर ध्यान, कुछ क्षण का मौन या कार्य की गहराई को समझने का प्रयास इसमें सहायक होता है। तीसरा अभ्यास भय से ग्रस्त होता है, तब वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह टिक नहीं पाता। लॉर्ड मोनवर्न की एकाग्रता इसलिए भी अटूट थी क्योंकि वे भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य में लीन रहते थे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना सीख लिया था और परिणाम को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दिया था। यह भाव मन को तनाव से मुक्त करता है और कार्य को सहज बना देता है। यह धारणा कि शांति केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही संभव है, पूरी तरह भ्रम है। वास्तव में शांति भीतर की अवस्था है, परिस्थितियों की नहीं। हमें भीतर शांति होती है, तब बाहर की अव्यवस्था भी हमें विचलित नहीं कर पाती। ऑपरेशन थियटर की भीड़ और शोर लॉर्ड मोनवर्न के लिए बाधा नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर एक मौन था। यही आंतरिक मौन एकाग्रता की भूमि है, जहाँ से सटीक निर्णय, स्थिर हाथ और स्पष्ट दृष्टि उत्पन्न होती है। एकाग्रता को विकसित करना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह निरंतर अभ्यास और अनुशासन से आती है। सबसे पहला अभ्यास है—स्पष्टता। हमें स्वयं से यह स्पष्ट करना होता है कि इस क्षण हमारा मुख्य कार्य क्या है। दूसरा अभ्यास

बाड़े कवि थे, पत्रकार थे पर उनके इन रूपों पर राजनीति कभी हावी हो तो पायी। इतना ही नहीं जब प्राथमिकताओं की बात आयी तो मप्र कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्होंने सत्ता में पद लेने के बजाए मां सरस्वती की साधना को ही प्राथमिकता दी। आजादी के बाद 30 अप्रैल, 1968 तक वे जीवित रहे पर सत्ता का लोभ उन्हें स्पशं भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं 1967 में भारतीय संसद द्वारा राजभाषा विधेयक पारित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को वह पदभूषण का अलंकरण भी लौटा दिया जो उन्हें 1963 में दिया गया था। वे समझौते के खिलाफ लोगों में चेतना जगाते रहे। उन्होंने लिखा है-

अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली

यह सुधार-समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली।

‘कर्मवीर’ के संपादक कैसे संपादक थे, इसे बताने के लिए उन्होंने कहा कि – “हम फक्कड़ सपनों के स्वर्गमंदा की लुटाने निकले हैं। किसी की फरमाइश पर जूते बनानेवाले चर्मकार नहीं हैं हम ।” यह निर्भीकता ही उनकी पत्रकारिता का भावभूमि का निर्माण करती थी। स्वाधीनता आंदोलन की आँच को तेज करने में उनका कर्मवीर अग्रणी बना। कम ही लोग जानते होंगे कि दादा को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके संपादकीय कार्यालय यानी घर पर तिरसूर भार छोपे गए, तलाशियां हुयीं। 12 बार वे जेल गए। कर्मवीर को अर्थाभाव में कई बार बंद होना पड़ा। लेखक से लेकर प्रूफ रीडर तक सबका कार्य वे स्वयं कर लेते थे। पत्रकारिता के लिए राष्ट्रसेवा और समाज के जागरण का ही एक माध्यम थी। भरतपुर के संपादक सम्मेलन में वे पत्रकारिता जगत का आह्वान करते हुए कहते हैं-“यदि समाचार पत्र संसार की एक बड़ी ताकत है तो उसके सिर जोखिम भी कम नहीं है। पर्वत की जो शिखरें हिम से चमकती हैं और राष्ट्रीय रक्षा की महान दीवार बनती हैं, उन्हें ऊंची होना पड़ता है। जगम में समाचार पत्र यदि बढ़प्पन पाए हुए है, तो उनकी जिम्मेदारी भी भारी है बिना जिम्मेदारी के बढ़प्पन का मूल्य ही क्या है ?”

# पारिस्थितिकी को नुकसान की जवाबदेही तय हो

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन के अंतर्गत आने वाली फूलों की घाटी देश-दुनिया में मशहूर है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर है। धरती का और आग की तीव्रता व भयावहता के आकलन के अलावा आपदा प्रबंधन के बीच समन्वय के बाद ही कर सकेगा। वायु सेना और वन विभाग बांबी बकेट आपरेशन के मुद्दे पर सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो के मामले में बहस यह बेहद संवेदनशील जगह बीती नौ जनवरी से लगी आग से लगातार धधक रही है। फूलों की घाटी में सबसे पहले पेनावडी और भ्यूंडार रेंज की पहाड़ियों पर आग लगी थी। समस्या यह है कि अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के बीच स्थित ऊंची चट्टानों, पेड़-पत्थर गिरने और जलते पेड़ों के चलते यहां राहत व वनकर्मियों का आग बुझाने के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। यहां न सड़क है और न पैदल रास्ता। एसडीआरएफपी भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही। वहीं अत्याधुनिक उपकरणों व संसाधनों का अभाव है। सूखी झाड़ियां, पत्तियां, सूखे पेड़ भी आग को फैला रहे हैं। जंगलों में धुंए का गुब्बारा और लपटें दिखाई देती हैं। आग नंदा देवी पार्क के नीचे के इलाके में हरे पेड़ों तक पहुंच गयी है। जबकि प्रशासन का दावा है कि फूलों की घाटी का निजमुला घाटी व गौणा गांव के जंगलों में लगी आग पर आंशिक रूप में काबू पाया है। लेकिन अभी 15 हैक्टेयर से ज्यादा इलाका धधक रहा है। हकीकत यह है कि नीचे की ओर से यह कहता है कि “यह महादेव, जो मेरे समझे और किसी का अहित न करे। इस व्रत में संध्या के समय दीपक जलाकर “ॐ नमः शिवाय” का जप करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि आत्मा की गुंज है। जब यह मंत्र श्रद्धा और विश्वास के साथ जपा जाता है, तो मन की अशांति धीरे-धीरे शांत होने लगती है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में किया गया मंत्र जप सामान्य समय की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि उस समय स्वयं महादेव की उपस्थिति मानी जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत का प्रभाव विशेष रूप से वैवाहिक जीवन पर देखा जाता है। शिव और पार्वती को आदर्श दंपति माना गया है। उनकी आराधना करने से पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ती है। जिन दंपतियों के जीवन में कलह या दूरी है, उनके लिए यह व्रत नई ऊर्जा और मधुरता का संचार करता है। वहीं जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत शुक्र दात की शांत

करने का आध्यात्मिक उपाय माना जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ मांगना नहीं, बल्कि समर्पण है। जब भक्त शिव से यह कहता है कि “यह महादेव, जो मेरे समझे और किसी का अहित न करे। इस व्रत में संध्या के समय दीपक जलाकर “ॐ नमः शिवाय” का जप करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि आत्मा की गुंज है। जब यह मंत्र श्रद्धा और विश्वास के साथ जपा जाता है, तो मन की अशांति धीरे-धीरे शांत होने लगती है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में किया गया मंत्र जप सामान्य समय की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि उस समय स्वयं महादेव की उपस्थिति मानी जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत का प्रभाव विशेष रूप से वैवाहिक जीवन पर देखा जाता है। शिव और पार्वती को आदर्श दंपति माना गया है। उनकी आराधना करने से पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ती है। जिन दंपतियों के जीवन में कलह या दूरी है, उनके लिए यह व्रत नई ऊर्जा और मधुरता का संचार करता है। वहीं जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत शुक्र दात की शांत

इस लापरवाही के लिए जवाबदेह तंत्र यह क्यों नहीं सोचता कि पहाड़ नहीं रहेंगे, वन संपदा इसी तरह आग की सिमिधा बनती रहेगी, तो ग्लेशियर खत्म हो जायेंगे, उस दशा में नदियां व अन्य जलस्रोत सूख जायेंगे और हम पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेंगे। तब क्या होगा? इस बारे में आमजन को भी सोचना होगा कि पहाड़ रहेंगे, वनस्पति रहेगी, हरियाली रहेगी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जिस तरह जलवायु परिवर्तन हमें चेतावनी दे रहा है, उसे देखते हुए हमें भी सावधानी बरतनी होगी। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल बचाव की जिम्मेवारी हम सबकी है। अरावली प्रकरण एक चेतावनी है कि अब भी समय है, संभल जाओ।



# दिल्ली से अलवर तक रफ्तार की नई लकीर, 164 किलोमीटर में ‘नमो भारत’ बदलेगी सफर की तस्वीर

(जीएनएस)। नई दिल्ली/अलवर। राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के बीच आवागमन को नई गति देने वाली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लेकर बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई है। केंद्र सरकार ने अलवर से दिल्ली को जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी है। लगभग 37 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना न केवल यात्रा को तेज और सुगम बनाएगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। लंबे समय से जिस रैपिड रेल कॉरिडोर का इंतजार किया जा रहा था, अब उसके जल्द जमीन पर उतरने की उम्मीद मजबूत हो गई है। अलवर से दिल्ली के बीच प्रस्तावित नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 164 किलोमीटर होगी। इस पूरे रूट पर 22 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से पांच स्टेशन भूमिगत होंगे। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मानेसर, धारुहेड़ा, बावल, रेवाड़ी होते हुए अलवर तक जाएगा। पहले चरण में रैपिड रेल सराय काले खां से धारूहेड़ा होते हुए बावल तक चलाई जाएगी। शुरुआत में यह योजना केवल धारूहेड़ा तक सीमित थी, लेकिन हरियाणा सरकार के अनुरोध और क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए इसे बावल तक विस्तार देने पर सहमति बनी और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। बावल में टर्मिनल स्टेशन बनाए जाने से आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों और



तेजी से विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह इलाका पहले से ही ऑटोमोबाइल, मैयूफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े उद्योगों का बड़ा केंद्र है। रैपिड रेल कनेक्टिविटी मिलने के बाद यहां निवेश बढ़ने, नए उद्योग आने और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही अलवर,

रेवाड़ी और मानेसर जैसे शहरों का सीधा और तेज कनेक्शन दिल्ली से जुड़ जाएगा, जिससे रोजाना सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में अलवर से दिल्ली तक सड़क मार्ग या सामान्य रेल से यात्रा निवेश बढ़ने, नए उद्योग आने और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही अलवर,

रैपिड रेल के शुरू होने के बाद यह दूरी काफी कम समय में तय की जा सकेगी। इससे नौकरीपेशा लोग, छात्र, व्यापारी और पर्यटक सभी लाभान्वित होंगे। खासकर वे लोग जो रोजाना दिल्ली-एनसीआर में काम करने के लिए अलवर, रेवाड़ी या आसपास के क्षेत्रों से आते-जाते हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।

## अहमदाबाद–तिरुच्चिरापल्ली और हापा–नाहरलगुन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

**जीएनएस)।** पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद-तिरुच्चिरापली साप्ताहिक स्पेशल और हापा-नाहरलगुन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विशेष क्रियाये पर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है: ट्रेन संख्या 09419 अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल, जिसे 26 फरवरी, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दिया गया है।

ट्रेन संख्या 09420 तिरुचिरापल्ली-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल जिसे 01 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 03 जनवरी, 2027 तक कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 09525 हापा-नाहरलगुन स्पेशल, जिसे 25 फरवरी, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 30 दिसंबर,



2026 तक कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 09526 नाहरलगुन-हापा स्पेशल, जिसे 28 फरवरी, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 02 जनवरी, 2027 तक कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 09419 और 09525 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 01 फरवरी,

2026 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

# सोना वायदा 9903 रुपये और चांदी वायदा 47987 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा 33 रुपये फिसला

मुंबई: देश के अग्रणी कमीडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमीडिटी वायदा, ऑफांस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 168610.81 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमीडिटी वायदाओं में 101068.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमीडिटी ऑफांस में 67529.56 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 46400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमीडिटी ऑफांस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3137.37 करोड़ रुपये का हुआ। कमीती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 86951.70 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 167899 रुपये के भाव पर खुलकर, 168000 रुपये के दिन के उच्च और 159239 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 169403 रुपये के पिछले बंद के सामने 9903 रुपये या 5.85 फीसदी की गिरावट के साथ 159500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 8569 रुपये या 5.76 फीसदी लुढ़ककर 140298 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 1066 रुपये या 5.69

फीसदी लुढ़ककर 17680 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 168990 रुपये के भाव पर खुलकर, 170954 रुपये के दिन के उच्च और 160697 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 10257 रुपये या 6 फीसदी लुढ़ककर 160697 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टैन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 182600 रुपये के भाव पर खुलकर, 185000 रुपये के दिन के उच्च और 173360 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 184425 रुपये के पिछले बंद के सामने 7806 रुपये या 4.23 फीसदी लुढ़ककर 176619 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 383898 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 389986 रुपये और नीचे में 351906 रुपये पर पहुंचकर, 399893 रुपये के पिछले बंद के सामने 47987 रुपये या 12 फीसदी लुढ़ककर 351906 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 47912 रुपये या 11.67 फीसदी औंधकर 362792 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 48277 रुपये या 11.74 फीसदी गिरकर 362782 रुपये



प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 9707.35 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 73.5 रुपये या 5.21 फीसदी औंधकर 1338 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 12.3 रुपये या 3.61 फीसदी घटकर 328.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 13.65 रुपये या 4 फीसदी लुढ़ककर 327.85 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 7.05 रुपये या 3.5 फीसदी लुढ़ककर 194.6



2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09086 इंदौर-सेंट्रल-इंदौर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। 2. ट्रेन संख्या 09057/09058

सरकार की मंशा इस परियोजना के जरिए केवल यातायात सुविधा बढ़ाने की नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के बीच संतुलित औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना है। रैपिड रेल कॉरिडोर के आसपास नए टाउनशिप, व्यावसायिक केंद्र और औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने की उम्मीद है। इससे जमीन और संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यटन की दृष्टि से भी अलवर और उसके आसपास के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी।

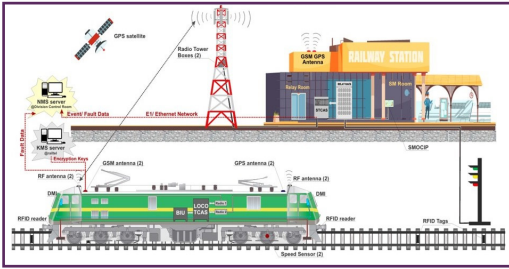
नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। तेज गति वाली ट्रेनें, सुरक्षित और सुविधाजनक स्टेशन, डिजिटल टिकटिंग, बेहतर निगरानी और पर्यावरण के अनुकूल ढांचा इस परियोजना की खास पहचान होगी। सड़क यातायात पर दबाव कम होने से प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है, जो दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। कुल मिलाकर, अलवर से दिल्ली तक नमो भारत रैपिड रेल को मिली मंजूरी को विकास की नई रेखा के रूप में देखा जा रहा है। यह परियोजना केवल दो शहरों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि राजस्थान और एनसीआर के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगी। आने वाले वर्षों में जब यह रैपिड रेल दौड़ती नजर आएगी, तब यह क्षेत्र के विकास, रोजगार और आधुनिक परिवहन का प्रतीक बनकर उभरेगी।

## पश्चिम रेलवे द्वारा विरार–सूरत–वडोदरा खंड पर कवच 4.0 को कमीशन किया गया ट्रेन संख्या 20907 दादर–भुज सायाजीनगरी एक्सप्रेस मुंबई से चलने वाली पहली कवच-सुसज्जित ट्रेन बनी



किलोमीटर लंबे मार्ग पर कवच प्रौद्योगिकी को कमीशन किया गया है। इस कॉरिडोर पर कवच को 49 स्टेशनों पर लागू किया गया है, जिसे 57 रेडियो संचार टावरों तथा लगभग 700 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का सहयोग प्राप्त है। कवच एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, जो सिगनल का खतरे की स्थिति में पार होना, अधिक गति तथा टक्करों जैसी मानवीय त्रुटियों से उत्पन्न जोखिमों को न्यूनतम करने में सहायक है। साथ ही, लेवल क्रॉसिंग पर स्वचालित सीटी (ऑटो-व्हिसलिंग) और लोको पायलट

के केबिन में सिगनल पहलू की पुनरावृत्ति जैसी विशेषताओं के माध्यम से प्रतिकूल मौसम और कम दृश्यता की परिस्थितियों में भी परिचालन सुरक्षा को और सुदृढ़ करता है। पश्चिम रेलवे द्वारा इससे पूर्व दिसम्बर 2025 में वडोदरा-अहमदाबाद खंड पर कवच प्रणाली को कमीशन किया गया था। विरार-वडोदरा खंड के कमीशन होने के साथ ही, वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर कुल 435 रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है।



द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कवच एवं लागत-प्रभावी सुरक्षा समाधान है, जो रेलवे सुरक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। पहले से कमीशन किए गए खंडों के अतिरिक्त, पश्चिम रेलवे के 2667 रूट किलोमीटर को कवर करने वाले अन्य कई खंडों पर कवच कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1435 करोड़ है। इसके अलावा, 2476

मांग किलोमीटर पर कवच कार्यों के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किए गए हैं, जो इस कार्यक्रम के व्यापक स्तर और तीव्र गति को दर्शाते हैं। चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ, पश्चिम रेलवे अपने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क पर कवच के विस्तार की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे समग्र रेल सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट होती है। अपने नेटवर्क पर उन्नत सुरक्षा प्रणालियों की तैनाती में निरंतर प्रगति के साथ पश्चिम रेलवे देश के लिए एक अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और भविष्य-तैयार रेलवे प्रणाली के निर्माण की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है।

997 रुपये पर खुलकर, 20 पैसे या 0.02 फीसदी की नरमी के साथ 991.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 51364.66 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 35587.05 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 8285.55 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 830.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 63.25 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 515.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिनों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 698.02 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1883.70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटररेट सोना के वायदाओं में 17628 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 116866 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 38286 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 563817 लोट और गोल्ड-टैन के वायदाओं में 63023 लोट

सूरत – मंगलुरु द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 09057 सूरत – मंगलुरु द्वि-साप्ताहिक स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09058 मंगलुरु – सूरत सूरत – मंगलुरु द्वि-साप्ताहिक स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 09057 सूरत – मंगलुरु स्पेशल के समय में संशोधन किया गया है और अब यह ट्रेन

सूरत से 19:40 बजे के बजाय 19:35 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09058 मंगलुरु – सूरत स्पेशल अब मंगलुरु से 22:10 बजे के बजाय 22:30 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 09085, 09086 एवं 09057 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 31 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

## भारत की तिजोरी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, विदेशी मुद्रा भंडार ने रचा नया इतिहास

**जीएनएस)।** नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर की आर्थिक अतिस्थिरताओं, भू-राजनीतिक तनावों और बाजारों में उत्तर-चढ़ाव के बीच भारत की आर्थिक मजबूती का एक और बड़ा प्रमाण सामने आया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 709.41 अरब डॉलर हो गया, जो अपने आप में एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। इससे पहले सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचा था, जिसे उस समय ऐतिहासिक माना गया था,

लेकिन मौजूदा आंकड़ों ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सित्त एक सप्ताह के भीतर विदेशी मुद्रा भंडार में 8.05 अरब डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज भंडार अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 709.41 अरब डॉलर हो गया, जो अपने आप में एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। इससे पहले सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचा था, जिसे उस समय ऐतिहासिक माना गया था,



ग्रामीणों ने तुरंत उसे उठाकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मराथ मंडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, मुकेश की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज गहन निगरानी में चल रहा है। सौरभ की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया, वहीं पिता बेसुध होकर जमीन पर बैठ गए। गांव में हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे अक्सर आसपास के इलाकों में खेलते या घूमते रहते हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जमीन में पड़ा एक विस्फोटक इतना बड़ा खतरा बन सकता है। लोगों ने प्रशासन और सेना से सवाल किया कि अभ्यास के बाद क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। घटना की सूचना मिलते ही बाराचट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे अक्सर आसपास के इलाकों में खेलते या घूमते रहते हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जमीन में पड़ा एक विस्फोटक इतना बड़ा खतरा बन सकता है। लोगों ने प्रशासन और सेना से सवाल किया कि अभ्यास के बाद क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित क्यों नहीं किया गया।

सैन्य अभ्यास हुआ था और ग्रामीणों को सावधान भी किया गया था। इसके बावजूद यह दुखद घटना घट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि यह जांच की जाएगी कि विस्फोटक अवशेष वहां क्यों और कैसे रह गए। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा घेरा और निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि क्षेत्र की घेराबंदी और निगरानी सख्त होती, तो शायद यह हादसा टल सकता था। घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी सहमे हुए हैं। यह हादसा केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्रों में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। एक मासूम किशोर की जान चली गई और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। गांव में आज भी सन्नाटा पसरा है और हर कोई यहीं सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं मासूम जिंदगियों को निगलती रहेंगी।



राज्य के 2666 गाँवों को मिलेगा अपना ग्राम पंचायत घर

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करने का समारोह आयोजित हुआ

► गुजरात की सभी ग्राम पंचायतों को उनका अपना पंचायत घर देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सेचुरेशन के विचार को साकार कराने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

► मुख्यमंत्री ने आणंद के भादण से ‘मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना’ लॉन्च की

► पंचायत मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा की प्रेरक उपस्थिति

► तहसील मुख्यालय हो और नगर पालिका न हो; ऐसे 114 गाँवों को ‘मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना’ के प्रथम चरण में समाविष्ट किया जाएगा, ऐसे गाँवों को शहरी समकक्ष सुविधा मिलने से उनका गुणात्मक एवं सर्वांगीण विकास होगा

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को आणंद के भादरण में आयोजित समारोह से राज्य की 2666 ग्राम पंचायतों के लिए उनके अपने ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए गाँवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो फोकस किया है, उसमें गुजरात अप्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का दिया गया सेचुरेशन अप्रोच गुजरात में साकार करने के लिए राज्य सरकार ने आगामी दिवसों में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को उनके अपने पंचायत घर-सह-पटवारी आवास देने का महत्वाकांक्षी निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन 2666 गाँवों में कुल 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर से ही सरकारी सेवाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्होंने इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में ‘मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना’ की राज्यव्यापी लॉन्चिंग भी की। श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के 114 तहसील मुख्यालयों वाले ऐसे

